



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 289]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 1984/आषाढ़ 1, 1906

No. 289]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 1984/ASADHA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 1984

का० आ० 459 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया  
निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए  
प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

यतः मैंने, जैल सिंह, भारत के राष्ट्रपति ने, 24 जून, 1983 को संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) के कतिपय उपबंधों का प्रवर्तन पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उस तारीख से छः मास की कालावधि के लिए निलंबित करते हुए, और कतिपय आनुपंगिक और पारिणामिक उपबंध बनाते हुए जो मुझे उपर्युक्त कालावधि में पांडिचेरी संघ राज्य का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबंधों के अनुसार चलाने के लिए आवश्यक और समीचीन लगे थे, एक आदेश किया था;

और यतः मैंने 23 दिसम्बर को पूर्वोक्त आदेश के अधीन  
निलंबित किये गए अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के  
निलम्बन के 24 दिसम्बर, 1983 से और छः मास की  
अवधि के लिए चालू रहने का एक और आदेश किया था;

और यतः मुझे पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक से  
एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उस रिपोर्ट तथा मुझे प्राप्त  
अन्य जानकारी पर विचार करने के पश्चात् मेरा यह समाधान  
हो गया है कि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में स्थिति अभी भी  
ऐसी बनी हुई है कि उस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अधि-  
नियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और  
उक्त संघ राज्य क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए यह आवश्यक है  
कि प्रथम उल्लिखित आदेश के अधीन मेरे द्वारा निलंबित किए  
गए अधिनियम के उपबंधों का प्रवर्तन निलंबित बना रहना  
चाहिए और उसमें किए गए आनुपंगिक और पारिणामिक  
उपबंध एक वर्ष की अवधि के परे प्रवृत्त बने रहने चाहिए;

अतः अब अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों  
और उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों  
का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा निर्देश देता हूँ :—

(क) कि प्रथम उल्लिखित आदेश के खंड (क)  
के फलस्वरूप निलंबित अधिनियम के उपबंधों

का प्रवर्तन निलंबित बना रहेगा और उस आदेश के खंड (ख) के फलस्वरूप बनाए गए आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध 24 जून, 1984 से छः मास की और कालावधि के लिए प्रवर्तित रहेंगे ; और

- (ख) कि प्रथम उल्लिखित आदेश, जिसे बाद में संशोधित किया गया, के खंड (क) में आने वाले "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष और छः मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

ह०/-

नई दिल्ली,

(जैल सिंह)

21 जून, 1984

भारत का राष्ट्रपति

[का० गं० यू०-11012/1/83-यू०टी०एल०]

हर्ष वदन गोस्वामी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 1984

S.O. 459(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

### ORDER

Whereas, I, Zail Singh, President of India, had on the 24th June 1983 made an Order suspending for a period of six months from that date the operation of certain provisions of the Government of Union Territories Act 1963 (20 of 1963) (hereinafter referred to as "the Act") in relation to the Union Territory of Pondicherry, and making certain incidental and consequential provisions which appeared to me to be necessary and expedient for administering the Union Territory of Pondicherry in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period;

And whereas I had on the 23rd December, 1983 made a further Order continuing the suspension of

operation of the provisions of the Act suspended under the aforesaid Order for a further period of six months with effect from the 24th December, 1983;

And whereas I have received a report from the Administrator of the Union Territory of Pondicherry and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that the situation in the Union Territory of Pondicherry continues to be such that the administration of that Union Territory cannot be carried on in accordance with the provisions of the Act and that for the proper administration of that Union Territory, it is necessary that the operation of the provisions of the Act suspended by me under the first mentioned Order should continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made therein should continue to operate beyond the period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby direct—

- (a) that the operation of the provisions of the Act suspended by virtue of clause (a) of the first mentioned Order shall continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made by virtue of clause (b) of the said Order shall continue to be operative, for a further period of six months with effect from the 24th day of June, 1984; and
- (b) that for the words "one year" occurring in clause (a) of the first mentioned Order, as subsequently amended, the words "one year and six months" shall be substituted.

Sd./-

(ZAIL SINGH)

PRESIDENT OF INDIA

New Delhi,

the 21st June, 1984

[No. U-11012/1/83-UTL]

H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.